



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर-342001

क्रमांक: F.37.(3)/वि.आ./जो.स्त.स./का.वि./2023/3850

दिनांक: 28/02/2022

कार्यवाही विवरण:-

नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के अधिस्तुता क्रमांक प.17(1)नविनि/अभियान/2021 दिनांक 25.11.2021 के द्वारा गठित जोन स्तरीय समिति की 01/2022 की बैठक दिनांक 13.02.2023 को उपपुस्त (जोन-1) की अध्यक्षता में उनके कक्ष में सम्पन्न हुई जिसमें उपस्थित सदस्य/अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा पर शिरो मूले निर्णय निम्नानुसार है :-

एजेण्डा संख्या	विषय
01.	राजस्व ग्राम श्रीयादे गांव के खसरा संख्या 82/3 के ले-आउट प्लान के संबंध में।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया-

01. आवेदित भूमि में विस्तृत लाईन (यदि कोई हो) तो उसके नीचे नियमानुसार रोपटी कोरिडोर छोड़ा जाना जावे। जिसकी सुनिश्चितता जोन द्वारा की जावे।
 02. प्रश्नगत भूमि में सरकारी भूमि सम्मिलित नहीं हो, की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे।
 03. उक्त ले-आउट प्लान अनुमोदन मौके पर निर्माण का नियमन/स्वीकृति नहीं है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानानुसार रोट बैंक छोड़े जाने होंगे तथा नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।
 04. ले-आउट प्लान की समस्त सड़कों को न्यूनतम 30 फीट रखा जावे।
- प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।

एजेण्डा संख्या	विषय
02.	राजस्व ग्राम श्रीयादे गांव के खसरा संख्या 25/1, 25/2 के ले-आउट प्लान के संबंध में।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत भूमि का मास्टर प्लान अनुसार भू-उपयोग आवासीय एवम् दरिजम् फेसलिटी आरक्षित है। अतः समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त ले-आउट प्लान में आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि का क्षेत्रविश्लेषण आयोजना शाखा द्वारा करते हुए प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या	विषय
03.	राजस्व ग्राम श्रीयादे गांव के खसरा संख्या 27, 27/6 के ले-आउट प्लान के संबंध में।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत भूमि का मास्टर प्लान अनुसार भू-उपयोग आवासीय एवम् दरिजम् फेसलिटी आरक्षित है। अतः समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त ले-आउट प्लान में, आवासीय, प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि का क्षेत्रविश्लेषण आयोजना शाखा द्वारा करते हुए प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

01.

एजेण्डा संख्या	विषय
04.	राजस्व ग्राम बासनी बैन्दा के खसरा संख्या 74/5 भूखण्ड संख्या 6, 7, 8 का पुनर्गठन के संबंध में।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया-

01. पट्टा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानानुसार रोट बैंक छोड़े जाने होंगे तथा नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।

सहायक नगर प्रियंका
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

मुकुला शेखावन
आर.ए.एस.
न्यायुक्त

02. मौके पर किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाने के संबंध में आवेदक से शपथ पत्र प्राप्त किया जावे व जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावे।
03. प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।
04. आवेदित भूखण्डों के पुनर्गठन किये जाने तथा आवेदकों से मूल पट्टा विलेख प्राधिकरण के पक्ष में समर्पित करवाये जाने व जोन स्तर से पुनर्गठित भूखण्डों के नवीन पट्टा विलेख जारी किए जावे। साथ ही प्रकरण में जरिये आम सूचना प्रकाशित कर विज्ञप्ति आमंत्रित की जावे तथा यदि कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो प्रकरण पुनः समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावे।

एजेण्डा संख्या	विषय
05.	राजस्व ग्राम बनावड के खसरा संख्या 418/2, 418/3 व अन्य के ले-आउट प्लान के संबंध में।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया-

01. ले-आउट प्लान में गैर मुमकिन ढाणी की भूमि का अंकन करते हुए उक्त भूमि को अनुमोदित मानचित्र का भाग नहीं माना जावे।
02. मानचित्र में आर्मी क्षेत्र से 50 मीटर दूरी का अंकन किया जावे।
03. आवेदित भूमि में विद्युत लाईन (यदि कोई हो) तो उसके नीचे नियमानुसार सेप्टी कोरिडोर छोड़ा जाना जावे। जिसकी सुनिश्चितता जोन द्वारा की जावे।
04. प्रश्नगत भूमि में सरकारी भूमि सम्मिलित नहीं हो, की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे।
05. उक्त ले-आउट प्लान अनुमोदन मौके पर निर्माण का नियमन/स्वीकृती नहीं है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानानुसार सेट बैक छोड़े जाने होंगे तथा नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।
06. ले-आउट प्लान की समस्त सड़कों को न्यूनतम 30 फीट रखा जावे।
07. प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।

एजेण्डा संख्या	विषय
06.	राजस्व ग्राम डिगाडी के खसरा संख्या 71 के ले-आउट प्लान के संबंध में।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया-

01. आवेदित भूमि में विद्युत लाईन (यदि कोई हो) तो उसके नीचे नियमानुसार सेप्टी कोरिडोर छोड़ा जाना जावे। जिसकी सुनिश्चितता जोन द्वारा की जावे।
02. प्रश्नगत भूमि में सरकारी भूमि सम्मिलित नहीं हो, की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे।
03. उक्त ले-आउट प्लान अनुमोदन मौके पर निर्माण का नियमन/स्वीकृती नहीं है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानानुसार सेट बैक छोड़े जाने होंगे तथा नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।
04. ले-आउट प्लान की समस्त सड़कों को न्यूनतम 30 फीट रखा जावे।
05. प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।

एजेण्डा संख्या	विषय
07.	राजस्व ग्राम डिगाडी के खसरा संख्या 118 के ले-आउट प्लान के संबंध में।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त प्रकरण में आवासीय क्षेत्रफल की जांच कर प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या	विषय
08.	राजस्व ग्राम डिगाडी के खसरा संख्या 200/153 के ले-आउट प्लान में संशोधन के संबंध में।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त मौका विवरण अनुसार प्रश्नगत ब्लॉक का संशोधन करने का निर्णय लिया गया।

तहसीलदार
 जोधपुर विकास प्राधिकरण

अधिशाषी अभियन्ता
 जोधपुर विकास प्राधिकरण

सहायक नगर नियोजक
 जोधपुर विकास प्राधिकरण

उपायुक्त (जोन-1)
 जोधपुर विकास प्राधिकरण

मंडलाधिकार
 आर.ए.एस.
 उपायुक्त

क्रमांक: F37.(3)/नि.आ./जो.स्त.स./का.वि./2023/3851-3856 दिनांक:- 28/2/23

प्रतिलिपी :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
2. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
3. निदेशक (आयोजना) महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
4. उपायुक्त जोन-1, जो.वि.प्रा., जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अधिशाषी अभियन्ता जोन-1, जो.वि.प्रा., जोधपुर
6. तहसीलदार जोन-1, जो.वि.प्रा., जोधपुर

सहायक नगर नियोजक
 एवं सदस्य सचिव, जोन स्तरीय समिति
 जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
 जोधपुर विकास प्राधिकरण
 जोधपुर